

2019/00000

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 47/2019 (अपील)

उनवान

औकार लाल पुत्र पांचूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम धनवां
तहसील दीगोद जिला कोटा

(अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक सुल्तानपुर वन मण्डल
कोटा

(रेस्पोंडेण्ट)

उपस्थित :- श्री ओमप्रकाश प्रजापत (अभिभाषक अपीलान्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी निर्णय दिनांक 20.08.2014 मिसल नम्बर 62/2014
न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सुल्तानपुर, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 26.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं न्याय तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम धनवा तहसील दीगोद के ख0 नं0 2 रकबा 0.80 हैक्टर भूमि अतिक्रमण करने पर निर्णय दिनांक 20.08.2014 से पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किये बगैर 5,000/-रूपये फसल की कीमत व 640/-रूपये शास्ती एवं एक माह 15 दिन का साधारण कारावास से दण्डित करने में त्रुटि की है जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि से कब्जा छोड़ दिया तथा तावान कि राशि जमा करवा दी है इय हेतु कब्जा छोड़ने व तावान की राशि जमा कराने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। साथ में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलान्ट को दिनांक 19.12.2019 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया है अपीलाधीन निर्णय कि सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.12.2019 को होने पर दिनांक 20.12.2019 को नकल प्राप्त की गई इस प्रकार दिनांक 19.12.2019 से पूर्व की अवधि जानकारी के अभाव डिले कण्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ दिनांक 20.08.2014 निरस्त करने का निवेदन किया गया।

2. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोंडेण्ट की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व रेस्पोंड के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलान्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट

को ग्राम धनवा तहसील दीगोद के ख0 नं0 2 रकबा 0.80 हैक्टर भूमि अतिक्रमण करने पर निर्णय दिनांक 20.08.2014 से पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किये बगैर 5,000/-रूपये फसल की कीमत व 640/-रूपये शास्ती एवं एक माह 15 दिन का साधारण कारावास से दण्डित करने में त्रुटि की है जो निरस्तनीय है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि से कब्जा छोड़ दिया तथा तावान कि राशि जमा करवा दी है इस हेतु कब्जा छोड़ने व तावान की राशि जमा कराने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है । अपीलान्ट ने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है वर्तमान में भी उसका कब्जा नहीं है । उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करेगा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ दिनांक 20.08.2014 निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

5. रेस्पोंडेण्ट की ओर से उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि ने का बहस में कथन है कि अपीलान्ट द्वारा वनभूमि पर कब्जा किया है। अपीलान्ट को उक्त अतिक्रमित आराजी से पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अपीलान्ट अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट में देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये हैं वे विश्वसनीय एवं सन्तोष जनक होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न क्षेत्रीय वन अधिकारी सुल्तानपुर की रिपोर्ट में मिसल नं0 109/12 निर्णय दि0 03.04.2012 से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। पत्रावली पर उपलब्ध स्थिति का अवलोकन अनुसार यह पाते हैं कि मौका पंचनामा नाका प्रभारी धनवां दिनांक 31.01.2014 से वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट द्वारा फसल की गई थी । इससे यह साबित है कि उसका विवादित आराजी पर अवैध रूप से कब्जा था । जिससे सिद्ध होता है कि अतिक्रमी का विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी होना सिद्ध होता है ।

7. अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते परन्तु चूंकि अपीलान्ट के कथनानुसार उसके द्वारा भूमि पर कब्जा छोड़ना अंकित किया है । अतः नरम रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट आंक्षिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट द्वारा तावान जमा कराने व कब्जा हटाने के संबंध में अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमित आराजी से वास्तविक रूप से मौके से कब्जा हटा लिया है एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करेगा के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में 15 दिवस में शपथ पत्र पेश करने तथा कब्जा हटाने की व तावान जमा कराने की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करने की शर्त पर सजा निरस्त की जाती है । अन्यथा सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रभावी रहेगा ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा